Non Payment of dues by JCI

111. SHRI DIPANKER MUKHER JEE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a)whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "JCI throttled by Maximum Support Price obligations non-payment of dues" which appeared in 'Economic Times' dated the 30th March, 1998;

(b)if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) the action plan of Government's to strengthen JCI?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) Yes Sir, JCI had never faced any fund constraint for conducting Price Support Operations during 1997-98. The Govt, provided adequate funds right from the beginning of the season and the corporation could commence operations from end July, 1997. The Govt, provided an amount of Rs. 26 crs. to JCI for procurement under Price Support Operation and arranged for payment of Rs. 7.00 crores on NJMC account against delivery of jute by JCI to NJMC in addition to providing Bank Guarantee for Rs. 33.00 crores. Due to adequate funds support, the Corporation could procure 9.85 lakh bales under price support operations and arrested the declining trend in prices.

(c) To strengthen the operational efficiency of the JCI the Govt, has advised the Corporation to reduce its manpower by 25% and to close down unviable purchase centres to bring down the overhead cost of the Corporation.

पटसन का लाभकारी मूल्य

112. **श्री दीपांकर मुखर्जी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान “2 मई 1998 के पूर्वांचल प्रहारी गुवाहटी” से “जूट का लाभकारी मूल्य न मिलने से विकट समस्या उत्पन्न” शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित पटसन उत्पादकों की समस्याओं से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किसानों के उत्पाद का लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (**श्री काशीराम राणा**) : (क) से (ग) जी हां। सरकार को पटसन किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद कीमत का भुगतान करने के बाद में उनके हितों की जानकारी है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय पटसन निगम (जे.सी. आई) ने जुलाई, 1997 के अंत से असम राज्य में मूल्य समर्थन प्रचालन शुरु किया था तथा सरकार से प्रदत्त पर्याप्त निधि सहायता से राज्य में आवकों के बढने के साथ ही अपनी खरीदारी आवक 20% तक बढ़ा दी है। वर्ष 1997-98 के दौरान जे.सी. आई. ने असम में चल रहे अपने 25 क्रय केन्द्रों से 12.63 लाख गांठों के कुल अनुमानित उत्पादन में से कच्चे पटसन तथा मेस्टा की कुल 1.62 लाख गांठों की खरीदारी की है।

कपड़ा मिलों की व्यवहार्यता के बारे में प्रतिवेदन

113. **श्री अखिलेश दास**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 120 कपड़ा मिलों से उन्हें फिर से चालू करने के बारे में प्रतिवेदन मांगे है;

(ख) यदि हां, तो आज तक प्राप्त प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है तथा उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्य अहै;

(ग) वे कौन-कौन सी कपड़ा मिलें हैं जिन्हें फिर से चालू करने योग्य बताया गया है; और

(घ) इस संबंध में भेजे गए प्रतिवेदनों के आधार पर की गई कार्रवाइयों का क्या ब्यौरा है?

वस्त्र मंत्री (**श्री काशीराम राणा**) : (क) से (घ) एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन.टी.सी. की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वागींण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसके लिए बी. आई.एफ. आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंज्जि के सकारात्मक बन जाने के बी. आई.एफ. आर के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।